Centre builds 'co-op stack' to deliver govt schemes via PACS

Our Bureau
New Delhi

On the lines of Agri Stack, the government is developing a "co-operative stack" by integrating various schemes in the sector which can be delivered through primary agricultural credit societies (PACS), ensuring greater benefits in rural areas.

Addressing a workshop on emerging technologies in PACS, organised by the PHD Chamber of Commerce, Ashish Bhutani, Secretary, Co-operation Ministry, said: "The ecosystem (of PACS) has been changed. We have reinvented the system, and it was highly necessary to remove opacity and lack of transparency in PACS."

He was referring to the digitisation process of PACS, funded by the Centre and executed through the National Bank for Agriculture and Rural Development (Nabard). This co-operative stack initiative aims to transform the rural institutional landscape by leveraging PACS as the primary vehicle for delivering government benefits, marking a significant shift from the current fragmented approach, where different schemes operate through separate channels.

INTENT TO MIGRATE

The technology integration within the co-operative stack includes AI-driven solutions, such as automated weather advisories that can help farmers make informed decisions about crop management and agricultural practices. "The intent now is to migrate to a co-operative stack, similar to Agri Stack, initiated by the Agriculture Ministry," he said.

Under the Agri Stack initiative, the government is trying to build a robust database of all farmers where each of them will have a unique identity card through which it will be easy to find out every detail, such as land records, crop pattern, fertilizer usage, whether benefits of government schemes have been availed or not and even their credit worthiness.

Bhutani also said digitisation had already begun transforming operations, and enhancing efficiency and accountability of PACS. Computerisation of 63,000 PACS are in advanced stages of completion, he said, adding that there were about 1.08 lakh PACS in the country with 13 crore members. Computerisation of another 17,000 PACS is also simultaneously going-on.

Though urban cooperative banks (UCBs) and regional cooperative banks (RCBs) were computerised, the same was not done in the case of PACS, and it got pace after the creation of a separate Ministry of Co-operation in 2021.

AGAINST PACS

Many of the government schemes in the rural areas are currently channelised though self-help groups (SHGs), but those are operating under circulars and notifications without formal legal backing.

"Many of the PACS are involved in the distribution of fertilizers and there are several complaints against them. Similarly, many SHGs are into credit disbursal or chit fund type activities. On the other hand, many PACS and SHGs are also doing a good job whether it is grain procurement, drone services or milk procurement. Now farmer producer organisations (FPOs) are also actively into business activities," a former head of a co-operative institution said.

Delivery of government schemes only through PACS may not be a good idea and with limited business opportunity in a village, there has to be a fine balance maintained among PACS, SHGs and FPOs, the former official said. He said SHGs were more effective as they were flexible and not burdened by government rules and regulations, whereas PACS are over-regulated through the Registrar of Co-operative Societies.

An inter-ministerial committee of Secretaries is working on establishing a single centre for dispensing all government scheme benefits in rural areas instead of the current system of multiple institutions handling different programmes. In this case, the panel has identified PACS as uniquely positioned to serve as the backbone of this co-operative stack.

"Technology is the way forward to link all schemes seamlessly through PACS. It is all the more reason to ensure that PACS embrace technologies as soon as possible," Bhutani said.

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Ujala Aaj Tak**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	02/07/2025	**Page no**	6
CCM	N/A		

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ० आशीष कुमार भूटानी ने आज नई दिल्ली में पीएचडी हाउस में आयोजित पैक्स में उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ॰ आशीष कुमार भूटानी ने आज नई दिल्ली में पीएचडी हाउस में आयोजित पैक्स में उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

चंडीगढ़ डा रमेश देहराज सम्पादक उजाला आज तक

चंडीगढ़ : इस अवसर पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रंजीत मेहता और सहकारिता मंत्रालय तथा भाग लेने वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एनएफडीबी, एनसीसीटी, इफको, कृभको आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे। दिनभर चले इस कार्यशाला में बारह राज्यों के पैक्स के एक सौ बाईस सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के ढाँचे में डिजिटल इंडिया के युग में पैक्स, सटीक कृषि उपकरणों का लाभ उठाना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट प्रौद्योगिकी, सहकारी फिनटेक और नीतिगत नवाचार तथा तमिलनाडु, जम्म-कश्मीर और मिजोरम में सफलता की कहानियों पर चर्चा शामिल थी।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ॰ आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में छह जुलाई दो हजार इक्कीस को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जो भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। सहकारी संस्थाएँ सौ वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं, इस तरह की पहली ऋण संस्था उन्नीस सौ चार में चेन्नई के पास स्थापित की गई थी। आज एक लाख से अधिक पैक्स हैं जिनके तेरह करोड़ से अधिक सदस्य हैं।

डॉ॰ आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि आज भी पैक्स की अल्पावधि ऋण सुविधाओं के माध्यम से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर बयालीस प्रतिशत हो गई है, हालांकि समग्र अल्पावधि ऋण में सहकारी ऋण संस्थानों की हिस्सेदारी में कुल मिलाकर पंद्रह प्रतिशत की कमी आई है। पर इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पैक्स जैसी संस्थाएँ ग्रामीण भारत के छोटे और सीमांत किसानों की सेवा कर-के स्पष्ट रूप से लाभकारी रही हैं।

डॉ॰ आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि देश में करीब दो हजार बैंकिंग लाइसेंस में से उन्नीस सौ लाइसेंस सहकारी क्षेत्र में हैं, सौ लाइसेंस अन्य बैंकों के पास हैं। सबसे छोटी ऋण संरचनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं

और ये नई तकनीक को अपनाने में अक्षम रही हैं, जिसके कारण सीमित बैंकिंग उत्पादों के साथ सहकारी बैंकों के कामकाज पर कुछ स्तर तक प्रतिबंध हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के गठन के बाद, सहकारी क्षेत्र के बैंकिंग मुद्दों को भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और आयकर विभाग के साथ उठाया गया है, और अब समय आ गया है कि सहकारी बैंकिंग संरचना नई तकनीकों को अपनाए, अपने संचालन में पारदर्शिता लाए और अपने मानव संसाधन मुद्दों को हल करके खुद को प्रतिस्पर्धी बनाए।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने कहा कि पहले पैक्स केवल ऋण या कृषि के लिए सामग्री प्रदान करने के लिए थे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने पैक्स को मजबूत करने और समाज के लिए उनकी भूमिका बढ़ाकर उन्हें व्यवहार्य बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स को सक्षम करने के लिए संघीय मॉडल के अनुरूप मॉडल उपनियम बनाए हैं, ताकि वे छब्बीस विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में खुद को

विविधता प्रदान करके आगे की आकांक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ जीवित रह सकें। सहकारिता मंत्रालय ने चार वर्ष की छोटी सी अवधि में सहकारिता के विभिन्न आयामों से जुड़ी साठ से अधिक पहल शुरू की हैं।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाया गया दूसरा बड़ा कदम सहकारिता के राष्ट्रीय डाटाबेस का निर्माण था, जो केंद्र और राज्यों दोनों के लिए सहकारी संस्थाओं में मौजूदा अंतर की पहचान करने और सहकारिता के सिद्धांतों पर राष्ट्र के विकास के लिए क्षेत्रों में मौजूद शून्य को भरने के लिए योजना बनाने में सक्षम बनाता है।

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मंत्रालय द्वारा सहकारी ऋण संस्थाओं यानी पैक्स के बुनियादी ढाँचे का कम्प्यूटरीकरण किया जाना तीसरा बड़ा कदम था। पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना में अब तक लगभग तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और अब लक्ष्य अस्सी हजार पैक्स का कम्प्यूटरीकरण करना और भारत सरकार की सभी योजनाओं को पैक्स के साथ एकीकृत करके उन्हें जीवंत आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं में बदलना है।

डॉ॰ भूटानी ने पैक्स डिजिटलीकरण के लाभों की तुलना रेलवे टिकट कम्प्यूटरीकरण से की और कहा कि डिजिटलीकरण से पैक्स की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता आएगी तथा यह अपने अस्तित्व के लिए व्यवहार्य और बड़े पैमाने पर समाज के लिए मूल्यवान बन जाएगा।

डॉ॰ आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि पैक्स राज्यों की एक ऐसी संस्था है जो एक अधिनियम द्वारा समर्थित है। राज्य सरकारों में ऐसे बहुत कम संस्थान हैं जो कानून द्वारा समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स में भारत सरकार के लिए ह्वन स्टॉप शॉपह्व बनने की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमें बस यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ये पैक्स अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाएँ।

डॉ॰ भूटानी ने कहा कि हमारे किसानों और ग्रामीणों को मौसम संबंधी सलाह, आपदा संबंधी सलाह, वर्षा पूर्वानुमान, कीट हमले संबंधी सलाह की आवश्यकता है और ऐसी नई तकनीकें उपलब्ध हैं, जिन्हें हमारे ग्रामीण भारत को जागरूक और मजबूत बनाने के लिए सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पैक्स को समावेशी, जीवंत और निर्बाध, कुशलतापूर्वक और पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए उभरती हुई तकनीकों की पहचान करना और उन्हें सिस्टम में एकीकृत करना मंत्रालय का काम है।

डॉ॰ आशीष कुमार भूटानी ने इस अवसर पर ह्एक पेड़ माँ के नामह्व के तहत एक पौधा भी लगाया और भाग लेने वाले सहकारी सदस्यों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का दौरा किया।कार्यक्रम में उपस्थित पैक्स सदस्यों ने अपनी चिंताओं को भी व्यक्त किया। तीन तकनीकी सत्रों के अलावा, जिनमें क्षेत्रीय आयुक्तों, स्टार्टअप्स, संबंधित मंत्रालयों और शिक्षाविदों के सदस्यों ने भाग लिया, आरसीएस के अलावा जम्मूह्कश्मीर, तमिलनाडु और मिजोरम के सचिवों द्वारा भी अनुभव साझा किए गए। कार्यशाला में भाग लेने वाले पैक्स को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ आज के कार्यक्रम का समापन हुआ।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Rishi Ki Aawaz**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	02/07/2025	**Page no**	4
CCM	N/A		

जल्द घोषित होगी राष्ट्रीय सहकारिता नीति : अमित शाह

जल्द घोषित होगी राष्ट्रीय सहकारिता नीति : अमित शाह

एजेंसी

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के उपलक्ष्य में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मंथन बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में देशभर के सहकारिता मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और सहकारिता विभागों के सचिवों ने भाग लिया। शाह ने घोषणा की कि बहुत शीघ्र राष्ट्रीय सहकारिता नीति लागू की जाएगी, जो वर्ष 2025 से लेकर 2045 तक देश के सहकारी क्षेत्र का मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि हर राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपनी सहकारिता नीति बनाएगा।

बैठक में प्राकृतिक खेती, ग्रामीण रोजगार सृजन और सहकारी संस्थाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया गया। शाह ने कहा कि देश की एक बड़ी आबादी के पास सीमित संसाधन हैं और उनकी छोटी-छोटी पूंजी को मिलाकर बड़ा कार्य केवल सहकारिता के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी आंकड़ा-संग्रह तंत्र (डेटाबेस) के माध्यम से यह पता लगाया जा सकेगा कि देश के किन गांवों में अभी तक कोई सहकारी संस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य है कि आने वाले पांच वर्षों में देश का कोई भी गांव ऐसा न रहे, जहां कोई सहकारी संस्था न हो। शाह ने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता विकास की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि हर राज्य कम से कम एक प्रशिक्षण संस्था को इस विश्वविद्यालय से जोड़े। बैठक में दो लाख बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की स्थापना, दुग्ध और मत्स्य सहकारिता के विस्तार, देश की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना तथा श्वेत क्रांति 2.0 जैसी पहलों पर भी विचार-विमर्श

किया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संस्था, राष्ट्रीय सहकारी जैविक संस्था और भारतीय बीज सहकारी संस्था जैसी नवगठित संस्थाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक में यह भी तय किया गया कि सहकारी बैंकों में अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी और उनके कार्यों का अधिकतम कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में अनुशासन, नवाचार और पारदर्शिता लाने के लिए मूल आदर्श अधिनियम (मॉडल एक्ट) को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। उन्होंने राज्यों से आह्वान किया कि सहकारिता के बीच सहयोग की भावना को अपनाकर देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में सहकारिता की भूमिका को मजबूत करें।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**The Impressive Times**	**Language**	English
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	02/07/2025	**Page no**	7
CCM	N/A		

Cooperation Secretary Dr. Ashish Kumar Bhutani Opens National Workshop on Emerging Tech in PACS

Cooperation Secretary Dr. Ashish Kumar Bhutani Opens National Workshop on Emerging Tech in PACS

Under the leadership of PM Narendra Modi and guidance of Home Minister Amit Shah Ji, formation of Ministry of Cooperation was a historic step

Ashok Sharma
info@impressivetimes.com

NEW DELHI: The Secretary, Ministry of Cooperation, Dr. Ashish Kumar Bhutani today addressed the inaugural session of the Workshop on "Emerging Technologies in PACS" organised in PHD House in New Delhi today. CEO of PHDCCI, Ranjeet Mehta and senior officers from Ministry of Cooperation and the participating states, representatives of NABARD, NCDC, NFDB, NCCT, NCCF,

IFFCO, KRIBHCO etc graced the occasion. The highlight of the workshop was that it was

DR. ASHISH KUMAR BHUTANI SAID THAT EVEN TODAY THE NUMBER OF PEOPLE WHO HAVE BENEFITTED THROUGH SHORT TERM CREDIT LENDING FACILITIES OF PACS HAS INCREASED TO 42% DESPITE AN OVERALL DECREASE TO 15% IN THE SHARE OF COOPERATIVE CREDIT INSTITUTIONS IN OVERALL SHORT-TERM LENDING

attended by 122 members of PACS from 12 States and Officers and Officials of Ministry of Cooperation, RCS of the States and various other related Ministries/Organisations. The discussion frameworks involved 'PACS in the age of Digital India', 'leveraging precision Agri tools', 'AI and IOT, Cooperative Fintech and Policy Innovations', and discussion on success stories in Tamil Nadu, Jammu and Kashmir and Mizoram. Speaking on the occasion the Secretary, Ministry of Cooperation Dr. Ashish Kumar Bhutani said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi Ji and the guidance of Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah Ji, the Ministry of Cooperation was formed on 6 July 2021 which was a historic step taken forward by Government of India. The Cooperative Institutions are more than 100 years old, first such credit institution dating back to 1904 near Chennai. Today there are more than 1 Lakh PACS with over 13 crore members. Dr. Ashish Kumar Bhutani said that even today the number of people who have benefitted through Short Term Credit lending facilities of PACS has increased to 42% despite an overall decrease to 15% in the share of Cooperative Credit institutions in overall short-term lending.

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Haryana Ki Aawaz**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	02/07/2025	**Page no**	3
CCM	N/A		

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक की

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक की

चडीगढ़(एचकेए ब्यूरो)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष - 2025 के उपलक्ष्य में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ -मंथन बैठक- की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। -मंथन बैठक- का सफलतापूर्वक आयोजन सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बैठक में देशभर के सहकारिता मंत्रियों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सहकारिता विभागों के सचिवों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंथन बैठक का उद्देश्य भारत में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा, उपलब्धियों का आंकलन और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करना है। अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना देश में बहुत पुराने सहकारिता के संस्कार को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ नए परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर की है। उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक परिवर्तन और नया परिदृश्य नरेन्द्र मोदी सरकार आने के बाद आया है। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 60-70 करोड़ लोग ऐसे थे, जिनके पास कई पीढ़ियों तक जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थीं। उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 तक के 10 साल के कालखंड में ही मोदी सरकार ने इन करोड़ों लोगों का जीवनस्वप्न पूरा कर दिया और इन्हें घर, शौचालय, पीने का पानी, अनाज, स्वास्थ्य, गैस सिलिंडर आदि सुविधाएं प्रदान कर दीं। श्री शाह ने कहा कि ये करोड़ों लोग अब अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए उद्यम करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पूंजी नहीं है और इन करोड़ों लोगों की छोटी-छोटी पूंजी से बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता सहकारिता है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए दो चीजें बेहद जरूरी हैं - जीडीपी और जीएसडीपी का विकास और 140 करोड़ लोगों के लिए काम का सृजन करना। उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति के लिए काम के सृजन के लिए सहकारिता के सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है और इसीलिए 4 साल पहले बहुत दूरदर्शिता के साथ सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। श्री शाह ने कहा कि हमें संवेदनशीलता के साथ देश के करोड़ों छोटे किसानों और ग्रामीणों के कल्याण के लिए सहकारिता को पुनर्जीवित करना ही होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि इस चिंतन और मंथन से तभी भला हो सकता है जब देश के 140 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त कर परिश्रम के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और इसे सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने 60 पहल की हैं। उन्होंने कहा कि इन पहल में से एक महत्वपूर्ण पहल है राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण, जिसकी मदद से हम वैक्यूम ढूंढ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस इसीलिए बनाया गया है कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तहसील स्तर की सहकारी संस्थाएं मिलकर ये देख सकें कि किस राज्य के किस गांव में एक भी सहकारी संस्था नहीं है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में देश में एक भी गांव ऐसा न रहे, जहां एक भी कोऑपरेटिव न हो और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहकारी डेटाबेस का उपयोग करना चाहिए। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत में सहकारिता आंदोलन के छिन्न-भिन्न होने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। उन्होंने कहा कि हमने समय के साथ कानून नहीं बदले, जो अब मोदी सरकार ने बदल दिए हैं। हमने सहकारिता की गतिविधियों को जोड़ा या समय के साथ बदला नहीं था। उन्होंने कहा कि पहले सहकारिता में सारी भर्तियां भाई-भतीजावाद से होती थीं और इसीलिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का विचार किया गया। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने आग्रह किया कि हर राज्य की कम से कम एक सहकारिता प्रशिक्षण संस्था, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े और राज्य के कोऑपरेटिव आंदोलन की ट्रेनिंग की पूरी हॉलिस्टिक व्यवस्था त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो रही। श्री शाह ने कहा कि कुछ ही समय में राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा भी होगी जो 2025 से 2045 तक, यानी लगभग आजादी की शताब्दी तक अमल में रहेगी। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय सहकारिता नीति के तत्वाधान में ही हर राज्य की सहकारिता नीति वहां की सहकारिता की स्थिति के अनुरूप बने और इसके लक्ष्य भी निर्धारित हों। उन्होंने कहा कि तभी आजादी की शताब्दी तक हम एक आदर्श कोऑपरेटिव स्टेट बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सहकारिता के क्षेत्र में अनुशासन, नवाचार और पारदर्शिता लाने का काम मॉडल एक्ट से होगा। उन्होंने कहा कि 2 लाख पैक्स के निर्णय के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लक्ष्य को फरवरी माह में ही समाप्त कर दिया जाए, तभी हम 2 लाख पैक्स के लक्ष्य तक समय से पहुंच सकेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसायटी पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब कोऑपरेटिव बैंक को हमने बैंकिंग एक्ट के तहत ले आए हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी लचीली अप्रोच अपनाते हुए हमारी कई समस्याएं दूर की हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बची समस्याएं तभी दूर हो सकती हैं, जब हम पारदर्शिता के साथ बैंक का संचालन और कर्मचारियों की भर्ती करें। उन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी कॅपरेटिव बैंकों के संचालन में और अधिक पारदर्शिता लाने की जरूरत पर बल दिया। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री अपने-अपने राज्यों में कृषि मंत्रियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, ताकि आम जनमानस के साथ-साथ धरती माता का स्वास्थ्य भी सुधरे। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि गुजरात में बहुत अच्छा और सफल प्रयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि यह हमारी राष्ट्रीय क्षमता की वृद्धि और संवर्धन, राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता की ताकत बढ़ाने और कोऑपरेटिव की शक्ति का संवर्धन करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। बैठक के दौरान सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहल के व्यापक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, नीति सुझावों और कार्यान्वयन रणनीतियों के सार्थक आदान-प्रदान की सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सहकार से समृद्धि' के विज़न के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ बैठक में किए गए विचार-विमर्श ने समावेशी विकास को प्राप्त करने में आपसी सहयोग और समन्वय के महत्व को रेखांकित किया। बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदुओं में देशभर में 2 लाख बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की स्थापना की प्रगति और ग्रामीण सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देना शामिल है। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के कार्यान्वयन पर भी बैठक के दौरान विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में भाग ले रहे प्रतिनिधियों ने दृष्टिकोण के तहत -अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025- में अपने योगदान को भी सामने रखा। तीन नवगठित राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी समितियों- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के कामकाज का समर्थन करने में राज्यों की भूमिका की समीक्षा पर भी बैठक में चर्चा की गई। इसके साथ ही एक टिकाऊ और सर्कुलर डेयरी अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से श्वेत क्रांति 2.0 पहल पर विचार विमर्श किया गया। आत्मनिर्भर भारत के तहत दालों और मक्का के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद से संबंधित नीतिगत मामलों पर भी प्रमुखता से चर्चा हुई।प्रतिनिधियों ने प्रमुख डिजिटल परिवर्तन पहलों जैसे कि पैक्स और रजिस्ट्रार सहकारी समितियों कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के कार्यान्वयन की समीक्षा की, जिसे एक प्रमुख नियोजन उपकरण के रूप में परिकल्पित किया गया है। बैठक के दौरान जिन अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, उनमें त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के माध्यम से क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सुधार शामिल थे। इनमें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए साझा सेवा इकाई (स्स्ध) का संचालन और शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन की स्थापना भी शामिल है। बैठक के सफल आयोजन ने भारत के सहकारी परिदृश्य को सहकारी संघवाद और सामूहिक विकास की भावना से प्रेरित आर्थिक विकास के एक मजबूत स्तंभ में बदलने के लिए केंद्र और राज्यों के साझा संकल्प की पुष्टि की है।

Downloaded from
SAMVAD